बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 134 ● नई दिल्ली ● मंगलवार 10 मार्च 2026 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

नांगलोई में डीटीसी बस ने कई लोगों को कुचला, दो की मौत; गुस्साई भीड़ ने किया पथराव और आगजनी

नई दिल्ली । नांगलोई इलाके में बेकाबू डीटीसी बस ने कुछ लोगों को कुचल दिया। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। आक्रोशित लोगों ने बस को रोक कर उसपर पथराव कर दिया। तोड़फोड़ करने के बाद भीड़ ने एक बस को आग के हवाले कर दिया। पथराव में छह बसों के शीशे टूट गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। पुलिस मौके पर मौजूद भीड़ को तितर-बितर कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक, आज सुबह करीब 9.45 बजे नजफगढ़ की तरफ से आ रही डीटीसी क्लस्टर बस ने एक स्कूटी, एक बाइक, एक रिक्शा और कुछ पैदल चलने वालों को टक्कर मार दी।

दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई की अपील पर सुनवाई, केजरीवाल-सिसोदिया समेत 23 को नोटिस जारी

नई दिल्ली ।

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा कुल 23 आरोपियों को आरोपमुक्त किया था। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पक्ष रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े केस की सुनवाई से रोक दिया है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ट्रायल कोर्ट में चल रही ईडी मामले की कार्यवाही को तब तक के लिए टाल दिया जाए, जब तक कि सीबीआई की इस याचिका पर फैसला नहीं हो जाता। वहीं, अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले में जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के स्टेटमेंट पर भी रोक लगाई। मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल मनीष सिसोदिया या अन्य किसी भी आरोपी के तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ था। अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। एसजी तुषार मेहता ने हाई कोर्ट में कहा कि यह मामला पूरी तरह से भ्रष्टाचार का है, इस मामले में आरोपियों द्वारा कुल 170 फोन नष्ट किए गए हैं। कोरोना

महामारी के दौरान जिस समय पूरा देश लॉकडाउन में था और आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंध था उस समय रिश्वत लेने देने के लिए प्राइवेट जेट तक का इस्तेमाल किया गया। ट्रायल कोर्ट के आदेश में अप्रूवर दिनेश अरोड़ा के बयानों को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। दिनेश अरोड़ा इस मामले में महत्वपूर्ण गवाह है। उन्होंने बताया है कि मीटिंग्स में क्या हुआ। दिनेश अरोड़ा के बयानों को आरोप तय करने के स्टेज पर स्वीकार किए जाने चाहिए। सीबीआई ने अपनी 974 पेज की लंबी याचिका में निचली अदालत के फैसले को चौंकाने वाला और गैरकानूनी करार दिया है। एजेंसी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया और जांच में सामने आए तथ्यों पर सही से विचार नहीं किया। याचिका में दावा किया गया है कि आबकारी नीति में साजिश रचकर कुछ निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का मामला स्पष्ट था, लेकिन निचली अदालत ने इसे नजरअंदाज कर दिया। मामला 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ा है, जिसे आप सरकार ने लागू किया था, लेकिन भ्रष्टाचार, रिश्वत और कार्टेलाइजेशन के आरोपों के बीच जुलाई 2022 में ही रद्द कर दिया गया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नीति को जानबूझकर इस तरह तैयार किया गया, ताकि शराब कारोबार में कुछ लोगों को एकाधिकार मिले और करोड़ों रुपये की रिश्वत का लेन-देन हुआ। 27 फरवरी 2026 को स्पेशल जज जितेंद्र सिंह की अदालत ने 598 पेज के आदेश में सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि सीबीआई का केस पूर्व नियोजित और बनावटी है। केवल बयानों पर केस बनाया गया। अदालत ने जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए थे। सीबीआई की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 9 मार्च यानी आज सुनवाई हुई। यह मामला हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की एकल पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

मालवीय नगर नस्लीय टिप्पणी मामला- नॉर्थईस्टर्न लोग गंदे कहने वाले दंपती की जमानत याचिका पर फैसला टला

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्वोत्तर की महिलाओं पर नस्लीय टिप्पणियों के आरोपी दंपती की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आरोपी दंपती की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और मंगलवार के लिए आदेश सुरक्षित रखा। आरोपी हर्ष प्रिया सिंह और रूबी जैन को 25 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की तीन महिलाओं पर नस्लीय गालियां दीं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। आरोपियों के वकील गौरव ने तर्क दिया कि यह मामला केवल पड़ोसियों के बीच हुए सहज विवाद का है, जिसमें दोनों पक्षों ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत नस्लीय भेदभाव का मामला नहीं है, क्योंकि आरोपी यह नहीं जानते थे कि शिकायतकर्ता आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं की

जनजातीय पहचान को लक्षित करने वाली कोई भाषा नहीं इस्तेमाल की। वकील ने यह भी तर्क दिया कि विवाद किराये के मकान के अंदर हुआ था, जो एससी/एसटी एक्ट की धारा 3 के तहत सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता। उन्होंने बताया कि पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल खुद आरोपियों ने की थी, क्योंकि वे भी शिकायतकर्ताओं की भाषा से डरे हुए थे। गौरव ने कहा कि घटना से जुड़े सभी सबूत पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए हैं और आरोपी पहले से ही जांच में शामिल हो चुके थे, इसलिए अब हिरासत में पूछताछ की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 (विभिन्न नस्लीय समूहों के बीच दुश्मनी फैलाने) को लागू न करने का भी तर्क दिया, क्योंकि वीडियो खुद शिकायतकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया और इसे व्यापक रूप से फैलाया। रूबी जैन की सेहत बिगड़ने का हवाला देते हुए वकील ने कहा कि जेल में उनका इलाज बाधित हुआ है। उन्होंने बीएनएसएस की धारा 480 के तहत महिलाओं को गैर-जमानती अपराधों में विशेष जमानत देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि रूबी की मेडिकल स्थिति उनके मूड और आक्रामकता को प्रभावित करती है, जिससे घटना के दिन उनका व्यवहार प्रभावित हुआ। शिकायतकर्ता लियी नोशी के वकील ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और जमानत मिलने पर आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। एक प्रमुख प्रत्यक्षदर्शी (एयर कंडीशनर लगाने वाला इलेक्ट्रीशियन) की अभी जांच नहीं हुई है। वकील ने आरोप लगाया कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की। घटना के तुरंत बाद उन्हें मकान मालिक के घर बुलाया गया, जहां मध्यस्थता के नाम पर दबाव डाला गया कि मामला शांत करें। वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। घटना के बाद रात में लोग उनके दरवाजे पर जुट गए थे। ऐसे में मणिपुर की एक लड़की को राज्य में जारी जातीय हिंसा के बीच दिल्ली छोड़कर घर लौटना पड़ा। धारा 196 बीएनएस पर उन्होंने कहा कि वीडियो शिकायतकर्ताओं ने नहीं अपलोड किया था। उन्होंने इसे दोस्तों को मदद मांगने के लिए भेजा था, लेकिन बाद में यह अनियंत्रित तरीके से सोशल मीडिया पर फैल गया। उन्होंने कहा, ÷आरोपी ने साफ कहा था तुम नॉर्थईस्टर्न लोग गंदे हो, यह कैसे किसी समुदाय पर हमला नहीं है?÷आरोपियों का जवाब और अन्य दावे गौरव ने डराने-धमकाने के आरोपों से इनकार किया और कहा कि ऐसी कोई आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि मामला राजनीतिक प्रभाव और मीडिया ट्रायल का शिकार है।

पीयूष गोयल बोले- कांग्रेस बहस से भाग रही

नई दिल्ली । केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- यह बहुत बुरा है कि कांग्रेस बहस से भाग रही है। स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कांग्रेस के कहने पर एक नोटिस एडमिट किया गया था, जिसे उन्होंने ठीक से ड्राफ्ट भी नहीं किया था। इसे ठीक किया गया और फिर एडमिट किया गया। आज की तारीख डिस्कशन के लिए सोच-विचार के बाद तय की गई थी। जब एक मोशन एडमिट हो गया और यह तय हो गया कि आज इस पर डिबेट होगी, तो वे उसी समय दूसरा मोशन ले आए। गोयल ने कहा कि कांग्रेस को पार्लियामेंट्री प्रोसेस या प्रोसीजर समझ नहीं आता, न ही वे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, उन्होंने डिबेट में हिस्सा लेने की कोई इच्छा नहीं दिखाई है। उन्होंने पहले ही मुद्दों की एक लिस्ट बना ली है, प्लेकार्ड लाए हैं, हाउस को डिस्टर्ब किया है और बेबुनियाद मामलों पर पार्लियामेंट का समय बर्बाद किया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन इतने जरूरी मुद्दे पर डिस्कशन होना था, विपक्ष ने डिबेट से भागने का फैसला किया, क्योंकि वे साफ तौर पर जानते हैं कि स्पीकर को पूरे हाउस का कॉन्फिडेंस है। यहां तक कि उनके अपने अलायंस के मेंबर भी इस डिबेट से बच रहे हैं। I.N.D.I.अलायंस के अंदर अफरा-तफरी है और कोई भी कांग्रेस को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इसीलिए वे एक और मोशन लाकर आज की बहस से भागने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के एक फेल लीडर हैं। उन्हें संविधान या नैतिकता की समझ नहीं है। उन्हें पार्लियामेंट्री प्रोसेस, प्रोसीजर या रूल बुक में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस तरह से वे काम करते हैं, उससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस एक दिशाहीन और पूरी तरह से फेल विपक्षी पार्टी है।

आइरिस लावन को भारत में पनाह दिए जाने पर क्या बोली सरकार? संसद में जयशंकर ने बताया- ईरानी समकक्ष मदद के आभारी

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने एक मानवीय कदम उठाते हुए ईरान के जहाज आईरिस लावन को केरल के कोच्चि बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि इस फैसले के लिए ईरान के विदेश मंत्री ने भारत का आभार भी जताया है। उन्होंने कहा कि इस समय ईरान के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन भारत ने स्थिति को देखते हुए मानवीय आधार पर यह फैसला लिया। विदेश मंत्री ने संसद को बताया कि 28 फरवरी को ईरान ने अपने तीन जहाजों को भारतीय बंदरगाहों पर रुकने की अनुमति मांगी थी। भारत ने 1 मार्च को इसकी मंजूरी दे दी। इसके बाद आइरिस लावन 4 मार्च को कोच्चि पहुंचा। जहाज के चालक दल को फिलहाल भारतीय नौसेना की सुविधाओं में रखा गया है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को लगा कि ऐसा करना सही और मानवीय कदम था। दरअसल, इससे पहले ईरान का एक और युद्धपोत आइरिस डेना डूब गया था। जानकारी के अनुसार यह जहाज श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 समुद्री मील दूर अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में टॉरपीडो से नष्ट हो गया था। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। संसद में बोलते हुए डॉ. जयशंकर ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष का असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाला हॉर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार तेल की उपलब्धता, कीमत और जोखिम, तीनों बातों को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है और भारतीय उपभोक्ताओं के हित को सबसे ऊपर रखा जाएगा। विदेश मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पश्चिम एशिया के कई नेताओं से संपर्क में हैं। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति, कतर के अमीर, सऊदी अरब और कुवैत के क्राउन प्रिंस, बहरीन के किंग, ओमान के सुल्तान, जॉर्डन के किंग और इस्राइल के प्रधानमंत्री से बात की है। अमेरिका के साथ भी भारत का राजनयिक स्तर पर संपर्क बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक लगभग 67,000 भारतीय अलग-अलग देशों की सीमाएं पार कर सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास पूरी तरह काम कर रहा है और कई देशों में भारतीय दूतावासों ने एडवाइजरी जारी की है। तेहरान में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। हालांकि, इस मुद्दे पर संसद में विपक्ष ने चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी भी की। विपक्षी सांसद तख्तियां लेकर सदन के बीच में आ गए और बहस की मांग करने लगे। उस समय सदन की अध्यक्षता कर रहे सांसद जगदंबिका पाल ने विपक्ष से नारेबाजी न करने और मंत्री की बात सुनने की अपील की।

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष को मिली अंतरिम जमानत, साकेत कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए की मंजूर

नई दिल्ली । साकेत कोर्ट ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को मनी लॉड्रिंग मामले में 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. इस पर साकेत कोर्ट ने कहा कि जवाद की पत्नी की तबीयत खराब है और मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है. जवाद अहमद सिद्दीकी ने अपनी पत्नी की सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की थी. जवाद ने अदालत से अर्जी में कहा उनकी पत्नी चौथे चरण के मेटास्टैटिक ओवेरियन कैंसर से पीड़ित हैं और नई दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में कीमोथेरेपी करा रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अल फलाह विश्वविद्यालय समूह के चेयरमैन जावद अहमद सिद्दीकी को स्थानीय अदालत द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दे सकता है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. ईडी ने कहा है कि मामले के कई अन्य पहलुओं की जांच अब भी जारी है ऐसे में सिद्दीकी जांच को प्रभावित कर सकते हैं. दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 61 वर्षीय सिद्दीकी को धन शोधन के मामले में दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी. सिद्दीकी पर फरीदाबाद स्थित शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा दी गई फीस से अवैध धन जुटाने और कॉलेजों की मान्यता व प्रमाणन के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप है. ईडी ने सिद्दीकी को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं. सिद्दीकी ने अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दी थी. सिद्दीकी की पत्नी कैंसर से पीड़ित हैं और 12 मार्च को उनकी कीमोथेरेपी होनी है. ईडी के अधिकारियों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि एजेंसी जल्द दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती देगी. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय अदालत ने सिद्दीकी को अंतरिम जमानत देते हुए एजेंसी की दलीलों पर 'गंभीरता से विचार नहीं किया' और पिछले साल 10 नवंबर को लाल किला के सामने हुए विस्फोट से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत सिद्दीकी के खिलाफ एक अन्य प्राथमिकी दर्ज है. ईडी, आरोपपत्र में लगाए गए आरोपों के बारे में भी उच्च न्यायालय को सूचित कर सकती है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा गिरफ्तार किए गए।

विपक्ष चर्चा की मांग करता है, फिर हंगामा करता है- जोशी

नई दिल्ली । लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन पर केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा- आज की काम की लिस्ट में साफ लिखा है कि हम इस पर चर्चा करेंगे। विपक्ष को प्रस्ताव लाना है। क्या प्रोसेस है? जब प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसके सपोर्ट में 50 लोग खड़े होने चाहिए, आज जब चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल ने बार-बार कहा कि अगर आप प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो मैं चर्चा की इजाजत देता हूं। जब स्पीकर के खिलाफ नो-कॉन्फिडेंस मोशन एजेंडा में है, तो आप बीच में दूसरा प्रस्ताव, दूसरा एडजर्नमेंट मोशन कैसे ला सकते हैं? कोई नियम है या नहीं? क्या कोई संविधान नहीं है? अगर हमें राहुल गांधी के कहे अनुसार सदन चलाना है, तो नियम क्यों होना चाहिए? यह कैसी थ्योरी है कि ये लोग पहले मांग करते हैं और बाद में रुकावट डालते हैं? जब मैं पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर था तो ऐसा कई बार होता था, उनका मानना है कि वे जो कहते हैं वही नियम है। जिस भी चीज पर चर्चा होनी है, वह पहले पीसी में तय होनी चाहिए।

नाम बदनाम ना करो!

हमें तो ईरान वालों के लिए सॉरी फील हो रहा है, बुरा सा लग रहा है। नहीं, नहीं, हम किसी को सॉरी नहीं बोल रहे हैं। हम किसी को सॉरी बोलने नहीं जाते। किसी को भी नहीं। फिर ईरान वाले तो आते ही किस गिनती में हैं। पहले कभी किसी से सॉरी बोला होगा तो बोला होगा, पर मोदी युग में तो सॉरी बोलने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मोदी कुल रीति सदा चली आयी, न इस्तीफा देब, न माफी मांगी जाई! जब मोदी जी ने 2002 के गुजरात के नरसंहार के लिए माफी नहीं मांगी, जब मोदी जी ने नोटबंदी के लिए माफी नहीं मांगी, जब मोदी जी ने कोरोना के टैम में दवा, आक्सीजन, अस्पताल में बैड के अभाव में तड़प-तड़प कर दम तोड़ने वालों के घरवालों से, लॉकडाउन में सैकड़ों किलोमीटर पैदल घिसट-घिसट कर शहरों से गिरते-पड़ते गांव-घर तक पहुंचने वाले मजदूरों से माफी नहीं मांगी, जब मोदी जी ने इलैक्टोरल बांड के गैर-कानूनी हथियार के जरिए, हजारों करोड़ रुपये की अवैध वसूली के लिए माफी नहीं मांगी और तो और सवा साल दिल्ली के बार्डरों पर डटे रहे किसानों से बिना अगर-मगर लगाए माफी नहीं मांगी, तो उनके प्रजा जन कैसे माफी मांगें? और माफी भी ईरान से। और वह भी सिर्फ इसलिए कि उस पर जब इलाके से बाहर वालों ने हमला किया, तो हमारे मुंह से विरोध के दो शब्द तक नहीं निकले। जब उसके सबसे बड़े नेता की निशाना साधकर हत्या कर दी गयी, तो हमारे नेता से शोक तक नहीं जताया गया। अब विरोध करना, शोक जताना और पड़ोसी का साथ देना और किसी वजह से ऐसा न कर पाएं तो माफी मांगना, ये सब तो नैतिक लफड़े हैं, जिनसे गांधी-नेहरू के टैम वाला पुराना भारत चला करता था। यह मोदी जी का नया भारत है, जो नैतिकता वगैरह के चक्करों में नहीं फंसता। बस बड़े सेठों का मुनाफा देखता है। तभी तो बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे, नया भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर बढ़ता चला जा रहा है। नैतिकता के चक्कर में हिचकने वालों को पीछे छोड़ता जा रहा है। नैतिकता के चक्करों में ही पड़े रहते, तब तो हमें भी पीछे छोड़कर कोई और आगे निकल गया होता। मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में 2047 तक विकसित देश बनने के रास्ते पर बढ़ते भारत के ऐसा करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमें भी बुरा सा लग रहा है। हमें भी बुरा लग रहा है कि हमले के पहले ही दिन अमेरिका के बमों ने मीनाब में छोटी बच्चियों के एक स्कूल को निशाने पर ले लिया और एक साथ 165 छोटी-छोटी बच्चियों को मौत की नींद सुला दिया। आखिर, इन छोटी बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हमें भी बुरा लग रहा है कि भारत में एक संयुक्त नौसैनिक आयोजन से लौटते हुए, ईरान के एक युद्धपोत को, जो एक प्रकार से निहत्था था, हमारे पास के समंदर में, जहां हम समुद्री सुरक्षा मुहैया कराने की ठेकेदारी के हौसले जताते आए थे, एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया और करीब एक सौ चालीस ईरानी नौसैनिकों को समंदर में मरने के लिए ही छोड़ दिया। वह तो श्रीलंका की नौसेना ने बत्तीस-चौंतीस नौसैनिकों को बचा लिया, वर्ना अपने बाकी साथियों के साथ ही उनकी भी जल-समाधि हो जाती। मरने वाले नौसैनिक तो भारत में ही एक समारोही आयोजन में हिस्सा लेकर अपने घर लौट रहे थे, उनके लिए बुरा लगता है। हम तो कहेंगे कि इस लड़ाई में ईरान में भी और ईरान पर हमला करने वालों तथा उनकी मदद करने वाले देशों में भी, जितने लोग भी मरे हैं, जितने भी घायल हुए हैं और जितना भी नुकसान हुआ है और आगे होगा, उसके लिए हमें बुरा लगता है। मोदी जी गलत थोड़े ही कहते हैं, हम बुद्ध के देश से हैं, न कि युद्ध के देश से! हमें ईरान वालों के लिए बुरा इसलिए और भी लग रहा है कि, वे बड़ी आसानी से खुद भी इस युद्ध की आफत से बच सकते थे और बाकी दुनिया को भी इस मुसीबत से बचा सकते थे। और जब हम बाकी दुनिया कहते हैं, तो शब्दश: सारी दुनिया को मुसीबत से बचाने की बात करते हैं। देखा नहीं, कैसे तेल के चक्कर में सारी दुनिया की इकोनॉमी की वाट लगी पड़ी है और वह भी सिर्फ एक हफ्ते की लड़ाई में। ट्रंप साहब की मानें तो उनकी तैयारी महीने भर से भी ज्यादा की है। यानी सारी दुनिया की इकोनॉमी का तो कबाड़ा ही होने वाला समझिए। पर ईरान वाले इससे आसानी से खुद भी बच सकते थे और बाकी दुनिया को भी बचा सकते थे। जाहिर है कि बाकी दुनिया में वो खाड़ी देश भी आते ही हैं, जो अमेरिका और ईरान की लड़ाई में सिर्फ इसलिए पिस रहे हैं कि अमेरिका को ईरान को निशाना बनाने के लिए उनके ठिकानों और तरह-तरह की सहूलियतों का सहारा लेना पड़ रहा है। उस बेचारे को खाड़ी की पंचैती करने के लिए, अपने लाव-लश्कर के साथ, हजारों किलोमीटर दूर से जो आना पड़ता है। ईरान वाले दुनिया को इस मुसीबत से बचा सकते थे, कैसे? सिंपल है। विश्व गुरु का दिखाया रास्ता अपना कर। ईरान को ज्यादा अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। बस भारत जो-जो करता रहा है, वही-वही करना था। स्वतंत्रता, संप्रभुता सब भूल जाते, जो ट्रम्प साहब कहते, यस सर कहकर मान लेते। ट्रम्प साहब कहते कि हमारा पठ्ठा नेतन्याहू जो कहे, पहले वह मानकर दिखाओ, तो नेतन्याहू जो कहता मानकर दिखा देते। ट्रंप-नेतन्याहू कहते कि ईरान में राजशाही को वापस ले आओ, तो राजशाही वापस ले आते। ट्रंप साहब कहते कि अपना तेल, हमारी बड़ी तेल कंपनियों के हवाले कर दो, तो कर देते। ट्रंप और नेतन्याहू कोई पागल तो हैं नहीं कि फिर भी ईरान पर हमला करते। ईरान को भी खाड़ी देशों के अमेरिकी अड्डों पर हमला नहीं करना पड़ता। पर नहीं, ईरान वालों को तो अपने ही मन की करनी थी। विश्व गुरु का उदाहरण सामने था, पर नहीं उन्हें तो विश्व बॉस की इच्छा अनसुनी करनी थी। सो भुगत रहे हैं और अपने साथ बाकी सारी दुनिया को भी भुगतवा रहे हैं। और लड़ाई में विश्व बॉस का कुछ बिगड़े न बिगड़े, कम से कम सारी दुनिया में विश्व बॉस के साथ-साथ विश्व गुरु की भी थू-थू तो करा ही रहे हैं। इरानियो, इतने जार सहकर अब तो संभल जाओ। कम से कम स्वतंत्रता, संप्रभुता वगैरह की गुजरे जमाने की बातें पब्लिक को याद दिलाकर, विश्व गुरु का नाम बदनाम ना करो।

संसद सत्र और भारतीय हित

आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है और देश घरेलू स्तर से लेकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न राजनीतिक झंझावतों से घिरा हुआ लग रहा है। अत: बहुत स्वाभाविक है कि संसद सत्र की बैठकों में विपक्ष व सत्तारूढ़ दलों के बीच जमकर खींचातानी हो। लोकसभा में जहां इसके अध्यक्ष श्री ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव पर आज सदन में लम्बी बहस होने के बाद मतदान हो, वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में विपक्ष पश्चिम एशिया में चल रहे ईरान-इस्राइल युद्ध से उपजे भारत को प्रभावित करने वाले सवालों को केन्द्र में लाए और सरकार को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास करे। इस सन्दर्भ में सबसे बड़ा सवाल भारत के प्रति अमेरिकी रुख को लेकर उठाया जा सकता है क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका खुलकर इस्राइल का साथ दे रहा है और जंग में बराबर का सहभागी है। पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में भारतीय संप्रभुता को लेकर खासी बहस इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से आधिकारिक बयान जारी कर कहा गया है कि उसने भारत को रूस से कच्चा पैट्रोलियम तेल खरीदने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी है। यह मोहलत उसने पिछले दिनों भारत के साथ हुए व्यापार समझौते के मोटे मसौदे की शर्तों के अनुरूप दी है परन्तु इसके साथ यह भी हकीकत है कि भारत-अमेरिका के बीच अभी तक तफसील में कारोबार की शर्तों का चयन नहीं हुआ है और इस मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बातचीत अभी होनी है। विपक्ष इसे भारत सरकार की कूटनीतिक व व्यापारिक असफलता बता रहा है और कह रहा है कि स्वतन्त्र भारत के इतिहास की यह अभूतपूर्व घटना है क्योंकि भारतीय हितों की नाप-जोख कोई दूसरा देश अमेरिका कर रहा है। दरअसल कूटनीतिक मोर्चे पर भारत बहुत सावधानी के साथ चलते हुए यह सिद्ध करना चाहता है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों का स्वयं संरक्षक है और अमेरिका को इस बारे में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। इस सन्दर्भ में मोदी सरकार के मौन को विपक्ष कम करके आंकने की गलती कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रमक कूटनीति को देखते हुए भारत शान्त रहते हुए अपने किये जा रहे कार्यों से उसका जवाब देना चाहता है इसीलिए सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि भारत द्वारा रूस से लगातार कच्चा तेल खरीदा जा रहा है। विगत 2 फरवरी को भारत व अमेरिका के बीच व्यापार समझौता होने की घोषणा वाशिंगटन से की गई थी जिसमें कहा गया था कि अब से भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और यदि वह खरीदारी करता है तो अमेरिका उसके आयातित माल पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने के लिए स्वतन्त्र होगा। इसमें यह भी कहा गया था कि अमेरिका अपने विभिन्न मन्त्रालयों की एक निगरानी समिति बनाकर देखेगा कि भारत कहीं रूस से तेल तो नहीं खरीद रहा। अमेरिका के इस दावे की तस्दीक हमें इसके बाद भारत सरकार द्वारा किये गये फैसलों से करनी होगी क्योंकि कूटनीति में जरूरी नहीं होता कि ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाये, बल्कि यह तय करना होता है कि अपने हितों को किस रास्ते से साधा जाये। यह रास्ता बिना आवाज निकाले अपने कामों का भी हो सकता है। अत: मोदी सरकार ने अमेरिका से बिना उलझे रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखा जिसे इकतरफा की गई अमेरिकी घोषणा के जवाब में देखा जाना चाहिए। इसके साथ दूसरा मसला हिन्द महासागर में ईरानी युद्ध पोत को अमेरिकी नौसैनिक पनडुब्बी द्वारा डुबोये जाने का है। यह युद्ध पोत भारत के निमन्त्रण पर विशाखापत्तनम में आयोजित विभिन्न देशों के संयुक्त नौसैनिक युद्धाभ्यास में भाग लेने आया था जो वह कार्यक्रम पूरा होने के बाद वापस अपने देश ईरान जा रहा था। अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध चल रहे युद्ध के दौरान इसे नष्ट किया। यह युद्ध पोत श्रीलंका के पास हिन्द महासागर के अन्तर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था। बेशक अमेरिका का यह कार्य निश्चित रूप से निन्दनीय था क्योंकि ईरान-इस्राइल युद्ध से हिन्द महासागर क्षेत्र अभी तक अछूता है। विपक्ष इस मुद्दे पर भी मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहा है परन्तु भारत ने ईरान के ही एक अन्य युद्धपोत को ही केरल के कोच्चि बन्दरगाह में लंगर डालने की इजाजत देकर अमेरिकी हिमाकत का अपने तरीके से जवाब दे दिया है। इस युद्धपोत में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ईरान ने भारत से विनय की थी कि वह उसे भारत में ठहरने की इजाजत दे जिससे युद्धपोत की खराबी दूर की जा सके। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के दौरान भारत के इस कदम का भी कमतर आंकलन नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल कूटनीति में यह भी नियम होता है कि अपने हितों को बिना आवाज किये भी साधो। भारत यदि यह रास्ता अपना रहा है तो इस पर क्यों हो-हल्ला किया जाये। हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के विश्व के सबसे शक्तिशाली देश होने की वजह से जिस तरह की नीतियां अपना रहे हैं उससे संयुक्त राष्ट्रसंघ से लेकर विश्व की अन्य बहुदेशीय पंचायतें अप्रासंगिक बन चुकी हैं अत: भारत को अपना रास्ता इन्हीं चट्टानी दरारों से होकर बनाना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार अमेरिका की नीतियों की वजह से पूरी दुनिया में भारी उथल- पुथल हो रही है और ऐसा लग रहा है कि इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पूरी विश्व व्यवस्था के क्रम को ही बदल कर रख देंगे। इसलिए भारत की संसद में जब बहस हो तो इस नई उभरती तस्वीर को भी सामने रखा जाये। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान पर यह युद्ध तब थोपा गया है जबकि वह इस बात पर राजी हो गया था कि परमाणु बम बनाने की गरज से वह यूरेनियम का परिशोधन नहीं करेगा।

सम्पादकीय...

आज की पीढ़ी

हर पीढ़ी अपनी चुनौतियों का सामना करती है। हमारे दादा-दादी ने युद्ध और अभाव देखे, हमारे माता-पिता ने आर्थिक संघर्ष और राजनीतिक परिवर्तन। लेकिन आज की युवा पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में बड़ी हो रही है, जो लगातार अस्थिर महसूस होती है। युद्धों, संघर्षों, आर्थिक मंदी, राजनीतिक तनाव और अचानक आने वाले वैश्विक संकटों की खबरें मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत पहुंच जाती हैं। छात्रों के लिए, विशेष रूप से उनके लिए, जो विदेश में पढ़ने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही विदेशों में पढ़ रहे हैं, इस अनिश्चितता ने उनके जीवन को उन तरीकों से आकार देना शुरू कर दिया है, जिनका सामना पिछली पीढ़ियों ने नहीं किया था। आज की दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई महसूस होती है। हजारों मील दूर होने वाला संघर्ष ईंधन की कीमतों, नौकरी के बाजारों, वीजा नीतियों और यहां तक कि विश्वविद्यालय परिसरों के माहौल को भी प्रभावित कर सकता है। उन युवा छात्रों के लिए, जो अभी अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू कर रहे हैं, यह वातावरण गहरी अनिश्चितता पैदा कर सकता है। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पहली चुनौती भावनात्मक है। घर छोड़ना कभी आसान नहीं होता। अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों की यात्रा करने वाला एक युवा छात्र पहले से ही घर की याद, सांस्कृतिक तालमेल और शैक्षणिक दबाव का सामना करता है। जब वैश्विक तनाव बढ़ता है, तो ये भावनात्मक तनाव और बढ़ जाते हैं। संघर्षों, वीजा प्रतिबंधों या देशों के बीच कूटनीतिक तनाव की खबरें न केवल छात्रों के लिए, बल्कि घर पर उनके परिवारों के लिए भी चिंता पैदा कर सकती हैं। विदेशों में होने वाली छोटी-सी घटना भी तब घबराहट पैदा कर सकती है जब वह टैलीविजन स्क्रीन और सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। एक युवा छात्र के लिए, जो पहले से ही असाइनमैंट, परीक्षा और अंशकालिक काम के साथ संघर्ष कर रहा है, यह अतिरिक्त भावनात्मक दबाव एकाग्रता और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। एक और चुनौती आर्थिक अनिश्चितता है। विदेश में पढ़ाई महंगी है। परिवार अक्सर अपने बच्चों को विदेशी विश्वविद्यालयों में भेजने के लिए अपनी जीवन भर की बचत खर्च कर देते हैं या बड़ा कर्ज लेते हैं। जब वैश्विक तनाव अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं, तो मुद्राओं में उतार-चढ़ाव होता है और जीवनयापन की लागत बढ़ जाती है। किराए, भोजन की कीमतों या ट्यूशन फीस में अचानक वृद्धि छात्रों के लिए गंभीर तनाव पैदा कर सकती है। स्नातक होने के बाद भविष्य में नौकरी के अवसरों के बारे में अनिश्चितता भी एक बड़ी चिंता बन जाती है। उदाहरण के लिए, कोविड-19 महामारी के बाद, कई अंतर्राष्ट्रीय छात्रों ने नौकरी के बाजारों को रातों-रात सिकुड़ते देखा। इंटर्नशिप गायब हो गईं, कंपनियों ने नियुक्तियां रोक दीं, और यात्रा प्रतिबंधों ने छात्रों के लिए घर लौटना या देशों के बीच आवाजाही करना मुश्किल बना दिया। देशों के बीच राजनीतिक तनाव भी छात्रों को सूक्ष्म तरीकों से प्रभावित कर सकता है। जब राष्ट्रों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, तो वीजा नियम कड़े हो सकते हैं, वर्क परमिट बदल सकते हैं और आव्रजन नीतियां अनिश्चित हो सकती हैं।

रैडक्लिफ ने तो दे दिया था हमें लाहौर

पाकिस्तानियों का आरोप था कि माउंटबेटन ने रेडक्लिफ पर दबाव डाला था कि वे भारत को फिरोजपुर और जीरा तहसीलें सौंप दें ताकि जम्मू-कश्मीर से संपर्क स्थापित हो सके। जो कुछ हुआ उस पर रेडक्लिफ को भी खेद था लेकिन वह इस कथन पर अडिग था कि इसने भारत को फिरोजपुर और जीरा इसलिए दिए क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ। उन पर कोई दबाव नहीं था। हालांकि, उनसे रिपोर्ट देने का आग्रह किया गया। 22 जुलाई, 1947 को रेडक्लिफ को लिखे पत्र में माउंटबेटन ने कहा कि लाहौर में उनकी पंजाब विभाजन समिति के साथ चर्चा हुई थी। समिति को दिए गए अपने आश्वासन का जिक्र करते हुए कि वे रेडक्लिफ को पंजाब सीमा निर्धारण पुरस्कार की यथाशीघ्र घोषणा की आवश्यकता के बारे में लिखेंगे, माउंटबेटन ने आगे कहा, 'पंजाब विभाजन समिति में इस बात पर जोर दिया गया कि यदि 15 अगस्त से ठीक पहले अंतिम समय में अवार्ड की घोषणा की गई तो अशांति का खतरा बहुत बढ़ जाएगा।' मुझे पता है कि आप इसे पूरी तरह समझते हैं लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस बारे में फिर से बात करूंगा और कहूंगा कि पुरस्कार की घोषणा के लिए आप जितने भी अतिरिक्त दिन का समय निकाल सकें, हम सभी उसके लिए आभारी होंगे। क्या 10 तारीख तक इसे जारी करने की कोई संभावना है?'

भारत विभाजन की जब-जब चर्चा चलेगी, नए-नए तथ्य सामने आते जाएंगे। प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर की एक कृति 'स्कूप' में इस विषय पर रोचक एवं अनूठी जानकारी दी गई है। विभाजन के प्रमुख केंद्र बिन्दु रैडक्लिफ के साथ श्री नैयर की वर्ष 1971 में लंदन में एक विस्तृत चर्चा हुई थी। सीधा व पहला सवाल तब यह पूछा गया था कि 'क्या आप सीमा-निर्धारण से सन्तुष्ट हैं?' तो रैडक्लिफ का तात्कालिक उत्तर था, 'मैंने तो लगभग पूरा लाहौर आपको दे दिया था मगर बाद में मुझे लगा कि यदि लाहौर भी न बचा तो पाकिस्तान के पास कोई भी बड़ा शहर नहीं बचेगा।' कुलदीप नैयर बताते हैं कि 1971 में यह मुलाकात रैडक्लिफ के आवास पर ही हुई थी। रैडक्लिफ ने स्वयं ही अपने आवास का द्वार खोला और अनौपचारिक रूप में स्वयं ही दोनों के लिए चाय बनाई। मुझे महसूस होने लगा था कि विभाजन के बाद की हिंसा के लिए स्वयं भी गहन पछतावे की मुद्रा में था। उसने यह भी स्वीकार किया कि 'मुझे इसे महत्वपूर्ण व संवेदनशील कार्य के लिए केवल 5-6 सप्ताह ही मिले। मौसम भी गर्मियों का था। मेरे लिए सीमा पर जाकर स्वयं सर्वेक्षण करना भी संभव नहीं था।' रेडक्लिफ ने बताया कि उसके पास समय बहुत कम था। सिर्फ 5-8 हफ्ते में भारत की परिस्थितियों से अनजान थी। पहली बार भारत आया था, अगर मुझे दो-तीन साल मिलते तो मैं बेहतर काम कर सकता था। मैंने बहुत पुराने नक्शों का इस्तेमाल किया क्योंकि गर्मी के कारण सीमा पर जाकर सर्वेक्षण करना असंभव था। मगर पाकिस्तानियों का यह आरोप गलत है कि मैंने हिंदुओं का पक्ष लिया। मैं मुसलमानों के प्रति अधिक उदार था और लाहौर देकर मैंने उन्हें और भी एहसानमंद बनाया। मैंने लगभग भारत को लाहौर दे ही दिया था लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं होगा। मैंने पहले ही कोलकाता को भारत के लिए आरक्षित कर रखा था। मैं यह मान चुका था कि लाहौर में हिंदू और सिख बहुसंख्यक थे और संपत्ति में भी काफी समृद्ध थे। फिर भी पाकिस्तान में बड़े शहरों की कमी के कारण उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अभी भी यह अस्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखाएं कैसे खींची गईं। हालांकि सीमा आयोग में चार और सदस्य थे दो भारत से, जस्टिस मेहर चंद महाजन और जस्टिस तेजा सिंह और दो पाकिस्तान से, जस्टिस दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुनीर, वे सभी सेवारत न्यायाधीश थे। यह निर्णय रेडक्लिफ ने लिया था क्योंकि आयोग विभाजित था, एक तरफ भारत के सदस्य थे और दूसरी तरफ पाकिस्तान के। रेडक्लिफ ने यह भी कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं निर्धारित करते समय मेरे पास कोई निश्चित नियम नहीं थे। सीमांकन करने से पहले ही मैंने वैसे पर्याप्त जानकारी एकत्र कर ली थी। 'मेरे काम का सबसे पेचीदा हिस्सा पंजाब और बंगाल के आखिरी हिस्से का धार्मिक आधार पर विभाजन करना था। इसलिए लाहौर को भारत को देने और फिर उसे पाकिस्तान के पक्ष में बदलने का उनका निर्णय समझ में आता था।' मैंने किसी न किसी तरह का संतुलन बनाए रखने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा रेडक्लिफ का नाम सुझाने का लाहौर को पाकिस्तान को देने के निर्णय में बदलाव से कोई लेना-देना नहीं था। मैंने पूछा, क्या आप भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई सीमा रेखाओं से संतुष्ट हैं? 'मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मेरे पास समय इतना कम था कि मैं इससे बेहतर काम नहीं कर सकता था। अगर मुझे उतना ही समय दिया जाता, तो मैं वही काम करता। हालांकि, अगर मुझे दो से तीन साल मिलते तो शायद मैं अपने काम में और सुधार कर पाता'। सीमांकन करने से पहले मैंने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों के ऊपर केवल एक बार डकोटा विमान उड़ाया था। उन्होंने कहा, 'यदि कुछ लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हुईं तो इसका दोष उन राजनीतिक व्यवस्थाओं में है जिनसे मेरा कोई लेना-देना नहीं है।' कुलपति नैयर ये बताते हैं कि जब वह मिलने गए तो रेडक्लिफ ने टाई के साथ जैकेट पहनी हुई थी, जो एक तरह का औपचारिक पहनावा था। लंबे समय तक न्यायाधीश रह चुके होने के कारण शायद विदेशियों से मिलते समय जैकेट पहनना उनकी आदत थी लेकिन उनके व्यवहार में कोई औपचारिकता नहीं थी। उनसे बातचीत के दौरान मैंने उन्हें एक सरल और स्पष्टवादी व्यक्ति पाया। जब मैंने उनके फ्लैट की घंटी बजाई तो उन्होंने खुद दरवाजा खोला। कमरा पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था जिसे उन्होंने शायद वर्षों में इकट्ठा किया होगा। बैठक का कमरा सादा लग रहा था। उनके पास कोई नौकर या नौकरानी नहीं थी क्योंकि वे खुद रसोई में जाते थे, जिसे मैं बैठक में सोफे से देख सकता था, चाय बनाने के लिए केतली को चूल्हे पर रखने के लिए। रेडक्लिफ ने यह भी बताया था कि वह सीमा आयोग के सदस्यों से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि वे सिर्फ अपने देश का पक्ष रख रहे थे। दोनों पक्ष अधिकतम क्षेत्र चाहते थे और उनके तर्क एक-दूसरे के विपरीत थे। रेडक्लिफ ने बताया कि पूर्वी बंगाल के एक मुस्लिम सदस्य ने उनसे निजी तौर पर मिलकर दार्जिलिंग को पाकिस्तान में शामिल करने की गुहार लगाई। उन्होंने कहा, 'मेरा परिवार हर गर्मी में दार्जिलिंग जाता है और अगर यह जगह भारत को मिल गई तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा।' रेडक्लिफ ने भारतीय सीमा आयोग के सदस्य मेहरचंद महाजन की बहुत प्रशंसा की, जो बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। उन्होंने महाजन की विद्वता और कानूनी ज्ञान से रेडक्लिफ को प्रभावित किया। 'उन्हें मेरा आभारी होना चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें लाहौर दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया, जबकि वह वास्तव में भारत का हिस्सा बनने लायक था। वैसे भी, मैंने हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों का अधिक पक्ष लिया।' उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस आरोप से हुआ था कि उन्होंने माउंटबेटन के दबाव में अपनी रिपोर्ट बदल दी थी। पाकिस्तानियों का आरोप था कि माउंटबेटन ने रेडक्लिफ पर दबाव डाला था कि वे भारत को फिरोजपुर और जीरा तहसीलें सौंप दें ताकि जम्मू-कश्मीर से संपर्क स्थापित हो सके। जो कुछ हुआ उस पर रेडक्लिफ को भी खेद था लेकिन वह इस कथन पर अडिग था कि इसने भारत को फिरोजपुर और जीरा इसलिए दिए क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस हुआ। उन पर कोई दबाव नहीं था। हालांकि, उनसे रिपोर्ट देने का आग्रह किया गया। 22 जुलाई, 1947 को रेडक्लिफ को लिखे पत्र में माउंटबेटन ने कहा कि लाहौर में उनकी पंजाब विभाजन समिति के साथ चर्चा हुई थी। समिति को दिए गए अपने आश्वासन का जिक्र करते हुए कि वे रेडक्लिफ को पंजाब सीमा निर्धारण पुरस्कार की यथाशीघ्र घोषणा की आवश्यकता के बारे में लिखेंगे, माउंटबेटन ने आगे कहा, 'पंजाब विभाजन समिति में इस बात पर जोर दिया गया कि यदि 15 अगस्त से ठीक पहले अंतिम समय में अवार्ड की घोषणा की गई तो अशांति का खतरा बहुत बढ़ जाएगा।' मुझे पता है कि आप इसे पूरी तरह समझते हैं लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इस बारे में फिर से बात करूंगा और कहूंगा कि पुरस्कार की घोषणा के लिए आप जितने भी अतिरिक्त दिन का समय निकाल सकें, हम सभी उसके लिए आभारी होंगे।

अमेरिका की कूटनीति नहीं दादागिरी!

आज दुनिया में हर ओर युद्ध, तबाही और अराजकता का दौर है। विकास की गति रुक रही है। अनिश्चितता का वातावरण है। अनेक देशों के नेता ही मवालियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जबकि विश्व के लोग हमेशा शांति और विकास चाहते हैं। कोई भी युद्ध नहीं चाहता। हर कोई यह चाहता है कि दुनिया के हर मुल्क में स्थिरता का माहौल बना रहे। इसी उठा-पटक में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सबसे आगे हैं। ट्रम्प ही क्यों, अमेरिका की तो फितरत ही रही है कि कोई बहाना ढूंढ कर कमजोर देशों को दबाना और उनके संसाधनों पर कब्जा करना। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट ने अमेरिका की कूटनीति और युद्ध रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर @sankofa360 से एक पोस्ट काफी वायरल हुई जिसमें लिखा है कि, प्रिय दुनिया, क्या तुम अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा झूठ बोलने से थक नहीं गए हो? क्या तुम उस साम्राज्य से थक नहीं गए हो जो खून और मौत की तलाश में नहीं रुकता? उन्होंने कोरिया (1950-1953) के बारे में झूठ बोला, ग्वाटेमाला (1954) के बारे में, इंडोनेशिया (1958), क्यूबा (1961), वियतनाम (1961-1975), लाओस (1964-1973), कांगो (1964), डोमिनिकन रिपब्लिक (1965), कंबोडिया (1969-1970), ग्रेनाडा (1983), लेबनान (1983-1984), लीबिया (1986), ईरान (1987-1988), पनामा (1989), इराक (1991, 1998, 2003), सोमालिया (1992-1994, 2007-वर्तमान), बोस्निया (1994-1995), सूडान (1998), अफगानिस्तान (1998, 2001), यूगोस्लाविया (1999), यमन (2002-वर्तमान), पाकिस्तान (2004), सीरिया (2014), लीबिया (2011), वेनेजुएला (2026), क्यूबा (2026), ईरान (2026) के बारे में झूठ बोला। अमेरिका या उसके सहयोगी कभी किसी बात पर सच्चे रहे हैं? दुनिया कब इनके झूठ से ऊब जाएगी? अब तो हमें पता होना चाहिए कि वैश्विक अशांति, मौत, अराजकता और विनाश के जिम्मेदार कौन हैं? जो दुनिया की स्थिरता के खिलाफ हैं? जो विश्व शांति के विचार से डरते हैं? तुम्हारी चुप्पी सहयोग है! अमेरिका वैश्विक मुसीबत पैदा करने वाला है। मौत और विनाश की मशीन! अमेरिकी साम्राज्य की तानाशाही के खिलाफ बोलो!!! यह पोस्ट न केवल अमेरिका की ऐतिहासिक गलतियों को उजागर करती है बल्कि दुनिया को जगाने का प्रयास भी करती है। आज, जब हम वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान जैसे देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप की नई लहर देख रहे हैं, यह स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका के फैसले गलत साबित हो चुके हैं। इन युद्धों ने न केवल लाखों जानें लीं बल्कि दुनिया को अस्थिरता की ओर धकेला। अमेरिका की इन गलतियों से यह पता चलता है कि वैश्विक समुदाय अब युद्धों से कितना ऊब चुका है? अमेरिका की विदेश नीति का इतिहास झूठ, हस्तक्षेप और युद्धों से भरा पड़ा है। 1950 के दशक से शुरू करें तो कोरियाई युद्ध (1950-1953) में अमेरिका ने उत्तर कोरिया के आक्रमण का बहाना बनाकर हस्तक्षेप किया लेकिन वास्तविकता यह थी कि यह शीत युद्ध की रणनीति का हिस्सा था। लाखों कोरियाई मारे गए लेकिन क्या अमेरिका की जीत हुई? नहीं, यह युद्ध आज भी कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव का कारण बना हुआ है। इसी तरह, 1954 में ग्वाटेमाला में अमेरिका ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को उखाड़ फेंका, क्योंकि वहां की भूमि सुधार नीतियां अमेरिकी कंपनियों को पसंद नहीं आईं। सीआईए के ऑपरेशन ने देश को दशकों की अस्थिरता में ढाल दिया। क्या यह फैसला सही साबित हुआ? नहीं, ग्वाटेमाला आज भी गरीबी और हिंसा से जूझ रहा है। 1950-60 के दशक से अमेरिका के झूठ की फेहरिस्त लंबी है। इंडोनेशिया (1958) में सीआईए ने विद्रोहियों को समर्थन दिया लेकिन असफल रहा। क्यूबा (1961) में 'बे ऑफ पिग्स' हमला एक बड़ी असफलता थी, जहां अमेरिका ने फिदेल कास्त्रो को हटाने की कोशिश की लेकिन खुद की किरकिरी हुई। वियतनाम युद्ध (1961-1975) तो अमेरिकी इतिहास का सबसे काला अध्याय है। अमेरिका ने 'टोंकिन की खाड़ी घटना' को बहाना बनाकर युद्ध शुरू किया, जो बाद में झूठ साबित हुआ। 58,000 अमेरिकी सैनिक और लाखों वियतनामी मारे गए। अमेरिका हारकर लौटा और वियतनाम आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है। क्या अमेरिका का फैसला सही था? नहीं, यह युद्ध अमेरिकी समाज को भी बांट गया। लाओस (1964-1973) और कंबोडिया (1969-1970) में गुप्त बमबारी ने लाखों लोगों को मार डाला और खमेर रूज जैसे आतंक को जन्म दिया। कांगो (1964) में अमेरिका ने वहां प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या में भूमिका निभाई, जो अफ्रीका की आजादी के प्रतीक थे। डोमिनिकन रिपब्लिक (1965) में हस्तक्षेप ने लोकतंत्र को कुचला। 1980 के दशक में भी यह सिलसिला जारी रहा। ग्रेनाडा (1983) में अमेरिका ने मेडिकल छात्रों की सुरक्षा का बहाना बनाकर आक्रमण किया लेकिन यह छोटे देश पर साम्राज्यवादी कब्जा था। लेबनान (1983-1984) में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई लेकिन कोई स्थायी शांति नहीं आई। लीबिया (1986) में कद्दाफी पर हमला, ईरान (1987-1988) में नौसेना संघर्ष, पनामा (1989) में नोरिएगा को हटाना ये सभी फैसले अमेरिका की ताकत दिखाने के लिए थे लेकिन उन्होंने क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ाई। इराक के खिलाफ 1991 का गल्फ वॉर, 1998 की बमबारी और 2003 का आक्रमण 'महाविनाश के हथियारों' के झूठ पर आधारित था। सद्दाम हुसैन को हटाया गया लेकिन इराक आज भी अराजकता में डूबा है, आईएसआईएस जैसे समूह पैदा हुए। सोमालिया (1992-1994, 2007-वर्तमान) में अमेरिकी हस्तक्षेप ने समुद्री डकैती और आतंकवाद बढ़ाया। बोस्निया (1994-1995) में नाटो हमले, सूडान (1998) में दूतावास बमबारी, अफगानिस्तान (1998, 2001) में तालिबान के खिलाफ युद्ध- ये सभी अमेरिका की 'आतंकवाद विरोधी' नीति के नाम पर थे लेकिन अफगानिस्तान से 2021 की शर्मनाक वापसी ने साबित किया कि 20 साल का युद्ध व्यर्थ था। यूगोस्लाविया (1999) में नाटो बमबारी ने कोसोवो को अलग किया, लेकिन जातीय तनाव आज भी है। यमन (2002-वर्तमान) में ड्रोन हमलों ने नागरिकों को मार डाला, पाकिस्तान (2004) में भी यही हुआ। सीरिया (2014) में आईएसआईएस के खिलाफ हस्तक्षेप ने देश को बर्बाद कर दिया। लीबिया (2011) में कद्दाफी को हटाने के बाद देश गृहयुद्ध में फंस गया और अब 2026 में वेनेजुएला, क्यूबा और ईरान पर झूठ। वेनेजुएला में अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए और विपक्ष को समर्थन दिया, दावा किया कि मदुरो तानाशाह है, लेकिन यह तेल संसाधनों पर कब्जे की कोशिश है। क्यूबा पर दशकों से प्रतिबंध लेकिन 2026 में नए आरोप लगाकर दबाव बढ़ाया जा रहा है। ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के बहाने हमले की धमकी, जबकि ईरान शांति समझौते चाहता है। ये सभी फैसले गलत साबित हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने न केवल लक्षित देशों को नुकसान पहुंचाया बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स बताती हैं कि युद्धों से करोड़ों लोग विस्थापित हुए, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं। यूक्रेन-रूस संघर्ष और इजराइल-फिलिस्तीन विवाद में अमेरिका की भूमिका ने दिखाया कि वह शांति दलाल नहीं, बल्कि युद्ध उकसाने वाला है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार भाटी ने कदम ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सराय पीपलथला एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार भाटी, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादस्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2019/...)

डीएम ने निर्माण कार्यो की धीमी रफ्तार पर जताई नाराजगी

मुरादाबाद।

जिलाधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली निर्माण परियोजना की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में उद्यान अधिकारी के उपस्थित न होने तथा उद्यान निरीक्षक द्वारा बैठक में प्रतिभाग करने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उद्यान निरीक्षक को बैठक में बाहर करते हुए तत्काल उद्यान अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कार्यदायीं संस्थाओं को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। कार्य की गुणवत्ता खराब

-कार्यदायी संस्थाओं को गुणवत्ता सुधारने की दी हिदायत

होने तथा मानक के अनुसार न पाये जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए पुनः निर्माण कराया जायेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी उपकरण सहित जाकर प्रोजेक्ट की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि 5 करोड़ से ऊपर के प्रत्येक प्रोजेक्ट की निर्माण गुणवत्ता की जांच हेतु वहां पर नियमानुसार जरूरी लैब भी स्थापित की जाये। यूपीसीएलडीएफ द्वारा राजकीय प्रक्षेत्र रौण्डा का

सुदृढ़ीकरण का कार्य 70 प्रतिशत होने पर जिलाधिकारी ने कार्य प्रगति बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। राजकीय प्रक्षेत्र पंडितपुर का सुदृढ़ीकरण कार्य पिछले माह पूर्ण होने का आश्वासन देने के बावजूद भी कार्य प्रगति 85.33 प्रतिशत होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए कार्य प्रगति बढ़ाकर समय से पूर्ण कर हैण्डओवर करने के निर्देश दिए। राजकीय पौधशाला फहेलउल्लागंज के सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रगति 88.35 प्रतिशत होने तथा कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 जनवरी 2026 होने पर जिलाधिकारी ने जल्द ही कार्यपूर्ण कर हैण्डओवर करने के निर्देश दिए। ग्रामीण अभियंत्रण द्वारा बनवाए जा रहे कस्तूरबा बालिका ठाकुरद्वारा में एकेडमिक ब्लाक एवं छात्रावास भवन निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 45 प्रतिशत होने पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि अपने जे.ई. से वार्ता कर कार्य की प्रगति बढ़ायें। उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम द्वारा बिलारी में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 78.1 प्रतिशत तथा निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि 31 मार्च 2026 होने पर जिलाधिकारी ने समय से कार्य पूर्ण कर हैण्डओवर करने के निर्देश दिए। गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशासनिक भवन, छात्रावास भवन एवं अन्य भवन निर्माण कार्य में 84.46 प्रतिशत भौतिक प्रगति होने पर जिलाधिकारी ने कार्य में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने राजकीय इंटर कालेज में मिनी स्टेडियम को टेक्नीकल रुप से सही बनाने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री मृणाली अविनाश जोशी, जिला विकास अधिकारी जी.बी. पाठक, जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रबन्धक उपस्थित रहे।

लोक अदालत न्याय पाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम

मुरादाबाद।

आम लोगों को सस्ता, त्वरित और सरल न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 14 मार्च को आयोजित होने वाली वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में सोमवार को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुरादाबाद के विश्राम कक्ष में बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों को अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण और जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। बैठक माननीय जनपद न्यायाधीश सै. माऊज़ बिन आसिम के मार्गदर्शन में आयोजित हुई।

इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी एवं अपर जिला जज मौहम्मद फिरोज़ ने की, जबकि संयोजन सिविल जज सीनियर डिवीजन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तपस्या त्रिपाठी ने किया। नोडल अधिकारी मौहम्मद फिरोज़ ने कहा कि लोक अदालत आम जनता के लिए न्याय पाने का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। इसमें आपसी सहमति से मामलों का निस्तारण किया जाता है, जिससे लोगों को लंबे मुकदमों, खर्च और समय की बचत होती है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे लोगों को लोक अदालत के बारे में व्यापक स्तर पर जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। सचिव तपस्या त्रिपाठी ने विभागाध्यक्षों से कहा कि लंबित मामलों को चिह्नित कर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जाए। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में बैंक ऋण, बिजली बिल, दुर्घटना दावा, पारिवारिक विवाद, राजस्व व अन्य समझौता योग्य मामलों का समाधान आपसी सहमति से कराया जाता है। बैठक में तहसीलदार सदर, कांठ, ठाकुरद्वारा नायब तहसीलदार बिलारी, एआरटीओ, सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प, आबकारी निरीक्षक, उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी आदि मौजूद रहे।

100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत खोजे जायेंगे टीबी रोगी

मुरादाबाद।

जिला क्षय रोग अधिकारी डॉ एन के कुरैचया ने बताया कि 100 दिवसीय सघन टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत होटल, छात्रावासों और भोजनालयों में भोजन पकाने और परोसने वाले, मेडिकल कॉलेज के छात्रों, स्वास्थ्य विभाग के डॉ और कर्मचारियों में टीबी रोग की खोज की जायगी।

इसके लिए टीबी रोग विभाग की टीमें होटल, छात्रावासों, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जा कर टीबी के लक्षणों के आधार पर टीबी रोग की स्क्रीनिंग कर टीबी रोग की अत्यंधुनिक मशीनों से जांच कराई जाएगी। टीबी के लक्षणों में मुख्य रूप से खांसी, बलगम आना , बलगम में खून आना, भूख कम लगना, वजन घटना, रात में सोते समय पसीना आना, बुखार आना, सीने में दर्द होना, थकान होना हैं। डीपीसी डॉ मोहम्मद जावेद ने बताया कि टीबी रोग की

इसके लिए टीबी रोग विभाग की टीमें होटल, छात्रावासों, मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में जा कर टीबी के लक्षणों के आधार पर टीबी रोग की स्क्रीनिंग कर टीबी रोग की अत्यंधुनिक मशीनों से जांच कराई जाएगी।

पुष्टि होने के 48 घंटे के भीतर उपचार प्रारम्भ कर दिया जायेगा, उन्होंने आगे बताया कि रोगी की सम्पूर्ण जानकारी निक्षय पोर्टल पर एंट्री रियल टाइम की जा एगी। डीपीपीएमसी मनोज कुमार ने बताया कि इसके प्रचार प्रसार के लिए स्कूलों, सामुदायिक बैठकों का आयोजन जनता में जनजागरूकता की जाएगी।

प्लेटफार्म पर मिला युवक का शव

मुरादाबाद। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर सोमवार को एक युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर जीआरपी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान संभल के हातिम सराय निवासी सोनू कश्यप (29) पुत्र भगवत सिंह कश्यप के रूप में हुई। सोनू लगभग तीन महीने से मुरादाबाद की काशीराम कॉलोनी में रह रहा था और पानी बेचने का काम करता था। सोनू के साथ रहने वाले एक युवक ने बताया कि वो नशा करने का आदी था। हालांकि, मृतक के परिजन ने हत्या का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसी ने सोनू की हत्या कर उसके शव को रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर फेंक दिया। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, युवक की मौत के सही कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा।

भाजपा महिला मोर्चा ने आयोजित किया नारी शक्ति सम्मान समारोह

बहराइच।

भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर महिला मोर्चा द्वारा नारी शक्ति सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें महिला खिलाड़ियों सोशल वर्कर, शिक्षक, तथा समाज में सेवाएं देने वाली महिलाओं को मोमेंटो प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एमएलसी डॉ प्रज्ञा त्रिपाठी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि इसमें तमाम महिलाएं रोजगार प्राप्त कर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं।

प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान दे रही है योगी शासन में महिलाएं अपने को अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं।विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्रीमती सुधा टेकरीवाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने महिलाओं के विकास हेतु 27 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया है।

आज देश में महिलाएं सभी प्रकार की नौकरियों में अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि देश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं का योगदान न हो। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला मोर्चा जिला संयोजक सोनी श्रीवास्तव ने किया । जबकि संयोजन डॉ अभिलाशा वर्मा एवं संचालन जिला महामंत्री उर्मिला शुक्ला ने किया इस अवसर पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा श्यामकरन टेकरीवाल जिला उपाध्यक्ष रणविजय सिंह जिला मंत्री सुनील श्रीवास्तव जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र कुमार मिश्रा पुष्पा चौधरी ज्योति सिंह मंजू गुप्ता मंजु निगम एकता जायसवाल तथा महिला मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रही।

धूमधाम से मनाया नगर विधायक रितेश गुप्ता का जन्मदिन

मुरादाबाद। शहर विधायक रितेश गुप्ता का 54 वां जन्मदिन आज कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया और बेंड बाजे की धुन पर जमकर डांस किया। कार्यकर्ताओं ने सदर विधायक रितेश गुप्ता को केक खिलाकर बधाई दी और उनके जन्मदिन पर उनके उ'ज्वल भविष्य की कामना की। सभी ने कहा कि 2027 में एक बार फिर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और सदर विधायक रितेश गुप्ता को बड़ी विजय दिलाकर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाये जाने की मांग करेंगे। सदर विधायक के मीडिया प्रभारी विपिन गुप्ता ने बताया कि आज विधायक के जन्मदिन पर सुबह से ही कार्यालय कार्यकर्ता पहुचने लगे थे उन्होंने बताया कि 6 बजे तक लगभग 500 केक कार्यकर्ताओं के साथ विधायक ने काटे। कार्यक्रम में शहर के वरिष्ठ लोग शामिल हुए बीजेपी कार्यकर्ता नगर विधानसभा क्षेत्र और जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग रितेश गुप्ता को बधाई देने पहुँचे।

चार साल के इज़ान ने रखा पहला रोज़ा

कम उम्र में दिखाई इबादत की मिसाल

मुरादाबाद। जनपद के आशियाना कॉलोनी के निवासी दानिश जमाल के चार वर्षीय बेटे इज़ान (मिशेल) ने माह रमज़ान में अपना पहला रोज़ा रखकर बड़ो की दुआएं बटोरी। इतनी कम उम्र में पूरे दिन रोज़ा रखकर ब'चे ने इबादत और सब्र की एक सुंदर मिसाल पेश की है। खास बात यह है कि यह नन्हा रोजेदार रोज़ा रखने के साथ-साथ मस्जिद में जाकर तरावीह की नमाज़ भी अदा करता है। इतनी छोटी उम्र में उसकी इबादत के प्रति लगन देखकर परिवार और आसपास के लोग बहुत खुश हैं और उसकी सराहना कर रहे है। परिवार के अनुसार बच्चा अपने माता-पिता को देखकर रोज़ा और नमाज़ के लिए प्रेरित हुआ। रमज़ान के इस पाक महीने में इस नन्हे बच्चे की इबादत लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बन रही है और सभी उसके अच्छे भविष्य के लिए दुआ कर रहे हैं।

सड़क पार कर रही महिला को बस ने मारी टक्कर, गंभीर

मुरादाबाद। महानगर के थाना मझोला क्षेत्र में दिल्ली रोड पर आज एक सड़क हादसा हुआ। दिल्ली से लखनऊ जा रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की एक बस ने रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सड़क पार कर रही एक गर्भवती महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल महिला को संभाला। उन्होंने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के अनुसार, महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस तेज रफ्तार से दिल्ली से लखनऊ की ओर जा रही थी। रिलायंस पेट्रोल पंप के पास सड़क पार करते समय बस ने गर्भवती महिला को टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के समय बस में चालक मजीद और परिचालक अंकित मौजूद थे। हादसे के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस सक्रिय हुई और महाराणा प्रताप चौक पर घेराबंदी कर बस को रोक लिया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर चालक और परिचालक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। हादसे की स'चाई जानने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। पुलिस घायल महिला की पहचान करने और उसके परिजनों को सूचित करने का प्रयास कर रही है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली में महिला उद्यमियों का महासम्मेलन, 10 हजार से अधिक प्रतिभागी हुए शामिल

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में महिला उद्यमिता को समर्पित एक भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया (एडीएसईआई) के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में देशभर से 10 हजार से अधिक महिला उद्यमियों ने भाग लेकर महिला नेतृत्व वाले आर्थिक विकास की नई तस्वीर पेश की. सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने किया. कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से आई महिला उद्यमियों ने भाग लेकर अपने अनुभव साझा किए और व्यापार में महिलाओं की बढ़ती भूमिका पर चर्चा की. केंद्रीय मंत्रियों ने अपने संबोधन में भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला

सशक्तिकरण और महिला-नेतृत्व वाले विकास के विजन का प्रत्यक्ष परिणाम है. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कैट और एडीएसईआई की पहल की सराहना करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर तैयार करने और उन्हें सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भारत की विकास यात्रा को और मजबूत बना रही है. केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सभी प्रतिभागियों को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए महिला उद्यमियों से अपनी सोच को और व्यापक बनाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के माध्यम से महिलाएं भारत की आर्थिक प्रगति में और बड़ा योगदान दे सकती हैं. सभा को संबोधित करते हुए कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि सम्मेलन में इतनी बड़ी संख्या में महिला उद्यमियों की भागीदारी प्रधानमंत्री मोदी के महिला-नेतृत्व वाले विकास के विजन की सफलता को दर्शाती है.

मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की दर्दनाक मौत

भिवाड़ी। राजस्थान के भिवाड़ी के पास हरियाणा सीमा से लगे इलाके में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। कापड़ियावास इलाके में स्थित सिग्नेचर ग्लोबल बिल्डर सोसाइटी में मिट्टी की खुदाई के दौरान अचानक मिट्टी धंस गई, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर उसके नीचे दब गए।

इस हादसे में अब तक 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है।

खुदाई के दौरान हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक दिल्ली-जयपुर हाईवे पर निर्माणाधीन सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी में जमीन की खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंस गया और वहां मौजूद कई श्रमिक उसके नीचे दब गए। हादसा होते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास

मौजूद लोगों ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी।

तुरंत शुरू हुआ राहत और बचाव कार्य

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। मिट्टी में दबे मजदूरों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक मलबे से 7 मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं। सभी शवों को भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका

प्रशासन के मुताबिक अभी भी कुछ लोगों के मिट्टी के नीचे दबे होने की आशंका है। इसी कारण मौके पर रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। बचाव दल के कर्मचारी जेसीबी और अन्य मशीनों की मदद से मिट्टी हटाकर लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर और मजदूर मलबे में फंसे मिले, तो मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

इलाके में फैली शोक की लहर

इस दर्दनाक हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और यह भी देखा जा रहा है कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन सही तरीके से किया जा रहा था या नहीं। फिलहाल राहत और बचाव दल की टीम मौके पर मौजूद है और मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है।

शिक्षा को अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने पर ध्यान जरूरी: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को देश की शिक्षा व्यवस्था को अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने की प्रक्रिया तेज करने का आह्वान करते हुए कहा कि कृत्रिम मेधा एवं स्वचालन जैसे विषयों पर ध्यान बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा, हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने की प्रक्रिया को और तेज करना होगा। हमें एआई, स्वचालन, डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजाइन-आधारित विनिर्माण जैसे विषयों पर ध्यान बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ऐसे में शिक्षा, कौशल और उद्योग के बीच

मजबूत तालमेल जरूरी है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि देश आज रोकथाम आधारित और समग्र स्वास्थ्य की परिकल्पना पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों में देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया गया है और सैकड़ों जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। आयुष्मान भारत योजना और आरोग्य मंदिर के जरिये स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हरेक गांव तक हो गई है। हमारी योग और आयुर्वेद पद्धतियां भी दुनिया भर में लोकप्रिय हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से बजट 2026-27 में प्रस्तावित विभिन्न बिंदुओं पर वेबिनार चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में यह वेबिनार भी आयोजित किया गया।

'वहीं बैठे रहोगे और घटते जाओगे', जेपी नड्डा बोले- विपक्ष फैला रहा अराजकता

नई दिल्ली। (वेबवार्ता) राज्यसभा में सोमवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान देने के लिए खड़े हुए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने शोर-शराबा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल संसद में अराजकता और हंगामा पैदा करना है। राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने शोक-संदर्भ और सूचीबद्ध दस्तावेज पेश होने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर को बयान देने के लिए आमंत्रित किया। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने बोलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर खरगे ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष भारत की आर्थिक स्थिरता और वहां काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा व आजीविका को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा और बदलते भू-राजनीतिक हालात पर लघु अवधि की चर्चा कराने की मांग भी की। सभापति ने खरगे से कहा कि वे बाद में उन्हें बोलने का मौका देंगे और विदेश मंत्री को अपना बयान देने के लिए कहा। जैसे ही जयशंकर ने बोलना शुरू किया, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और खरगे को पूरा बोलने देने की मांग करने लगे। इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विदेश मंत्री का बयान समाप्त होने के बाद सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार को गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को देश के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे लगातार मंत्रियों के जवाब के दौरान

दिल्ली दंगा मामला- शरजील इमाम को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को दिल्ली दंगा साजिश मामले में 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है. कोर्ट ने यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी है. एडिशनल सेशंस जज समीर बाजपेयी ने ये फैसला सुनाया. 20 मार्च 206 से 30 मार्च 2026 तक अंतरिम जमानत दी गई है. इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया. पिछले साल बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी शरजील ने जमानत मांगी थी लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट से उसे जमानत नहीं मिली थी. शरजील इमाम 2020 दिल्ली दंगा के साजिश मामले में आरोपी है, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए थे. शरजील जनवरी 2020 से जेल में बंद है. 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार उसे किया गया था और उस पर हिंसा भड़काने में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है.

ईरान जंग के बीच जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का फैसला

अब डिलीवरी के 25 दिन बाद ही बुक होगा दूसरा सिलेंडर

नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ा दिया है. सूत्रों के मुताबिक अब इसे 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है. ये फैसला ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को लेकर लिया गया है. सरकार ने कहा है कि अभी तक घरेलू गैस या डीजल-पेट्रोल की कोई कमी नहीं है. मंत्रालय ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को तीन दिन पहले ही 15 दिन से बढ़ाकर 21 दिन किया था, लेकिन अब 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है. यानी अब ग्राहकों को सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच 24 दिन का अंतर रखना होगा.

एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में उछाल

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच दो दिन पहले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 114.5 रुपये की बढ़ोतरी की गई. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) की वेबसाइट

के अनुसार, दिल्ली में अब गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर 913 रुपये में मिलेगा जबकि पहले इसकी कीमत 853 रुपये थी. एक साल में ये दूसरी बार है जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए. कीमत में बढ़ोतरी 7 मार्च से लागू हो चुकी है. इससे पहले पिछले साल अप्रैल में कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी. आईओसी की वेबसाइट के अनुसार, मुंबई में गैर-सब्सिडी वाली एलपीजी अब 912.50 रुपये, कोलकाता में 939 रुपये और चेन्नई में 928.50 रुपये की हो गई है. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों यानी 2016 में योजना शुरू होने के बाद से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पाने वाले 10 करोड़ से अधिक गरीब लोगों को एक साल में 12 बार 14.2 किलोग्राम के हर सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती रहेगी. होटल और रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल की जाने वाली कॉमर्शियल एलपीजी की कीमत 19 किलोग्राम के हर सिलेंडर पर 114.5 रुपये बढ़ाई गई है. अब दिल्ली में इसकी कीमत 1,883 रुपये है. यह बढ़ोतरी एक मार्च को 19 किलोग्राम के हर सिलेंडर पर 28 रुपये बढ़ाए जाने के बाद की गई है. इस साल वाणिज्यिक एलपीजी की दरों में 302.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

ईरान जंग पर विपक्ष का दोनों सदनों में हंगामा

नई दिल्ली।

संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के पहले दिन की लोकसभा की कार्यवाही खत्म हुई। विपक्ष ने अमेरिकी-इजराइल और ईरान जंग पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष जंग के बाद पश्चिम एशिया में बने हालातों का भारत पर असर पर चर्चा की मांग करता रहा। सरकार ने कहा कि विपक्ष स्पीकर ओम बिड़ला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई है, हम इस पर चर्चा करने पर तैयार हैं, विपक्ष चर्चा करे, लेकिन विपक्ष दूसरा मोशन ले आया है, जिसका विदेश मंत्री ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। इसके बाद सदन मंगलवार सुबह 11 बजे तक स्थगित किया गया। वहीं, आज विदेश मंत्री ने पहले राज्यसभा में और फिर लोकसभा में गल्फ देशों से भारतीयों की वापसी और एनर्जी संकट को लेकर तैयारियों के बारे में बताया।

चर्चा की मांग; सरकार बोली- स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर बहस के लिए तैयार

उन्होंने कहा- इस समय ईरान की लीडरशिप से कॉन्टैक्ट मुश्किल है, लेकिन भारत शांति और बातचीत के पक्ष में है। राज्यसभा में जब जयशंकर संबोधन दे रहे थे तब विपक्ष ने राज्यसभा का वॉक आउट किया। लोकसभा में उनके संबोधन के दौरान विपक्ष ने वी वॉन्ट डिस्कशन के नारे लगाए, खूब हंगामा किया। चेयर के बार-बार बोलने पर भी विपक्षी सांसद शांत नहीं हुए थे। राज्यसभा की कार्यवाही अभी जारी है।

विदेश मंत्री ने कहा- 67,000 नागरिक इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके

मौजूदा संघर्ष भारत के लिए भी चिंता की बात है। हम पड़ोसी हैं, और वेस्ट एशिया में स्थिरता बनाए रखना हमारी भी जिम्मेदारी है। खाड़ी देशों में एक करोड़ भारतीय रहते और काम करते हैं। ईरान में भी, कुछ हजार भारतीय पढ़ाई या नौकरी के लिए हैं। यह इलाका हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है और इसमें तेल और गैस के कई जरूरी सप्लायर शामिल हैं। सप्लाई चेन में रुकावटें और अस्थिरता गंभीर मुद्दे हैं। हमने दो भारतीय नाविकों (मर्चेंट शिपिंग) को खो दिया है, और एक अभी भी लापता है। मुंबई के शिपिंग डायरेक्टरेट जनरल ने 14 जनवरी को भारतीय नाविकों से कहा था कि वे एम्बेसी की एडवाइजरी मानें और किनारे पर बेवजह आने-जाने से बचें। वेस्ट एशिया से हमारे लोगों को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 8 मार्च तक हमारे लगभग 67,000 नागरिक इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुके हैं। संबंधित मंत्रालय जवाब देने के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लड़ाई लगातार बढ़ रही है। इलाके में सुरक्षा की स्थिति काफी खराब हो गई है। असल में, लड़ाई दूसरे देशों में भी फैल गई है। इससे तबाही और मौतें बढ़ रही हैं। इजराइल-यूएस और ईरान के बीच लड़ाई जारी है, बल्कि कुछ खाड़ी देशों पर हमले भी हुए हैं। ईरान में लीडरशिप लेवल पर कई लोग मारे गए हैं, साथ ही इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुआ है। इस समय लीडरशिप लेवल पर ईरान के साथ कॉन्टैक्ट करना साफ तौर पर मुश्किल है। ईरान के विदेश मंत्री ने ईरानी वॉरशिप लावन को कोच्चि पोर्ट पर डॉक करने की इजाजत देने के भारत का शुक्रिया अदा किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाएगा विपक्ष- सूत्र

नई दिल्ली। विपक्ष देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विपक्ष संसद के निचले सदन में ही सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है. बताते चलें कि मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य को लेकर निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्षी दलों के निशाने पर हैं. इस समय चुनाव आयोग के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खोल रखा है. तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव से पहले एसआईआर के जरिए बड़ी संख्या में वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं. ऐसा देश में पहली बार होगा कि सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आएगा. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीएमसी की अगुवाई में सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष जुटा है. आर्टिकल 324(5) के तहत सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए लोकसभा में 100 या राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है. नोटिस के बाद कमिटी गठित की जाती है. लोकसभा अध्यक्ष को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के बाद विपक्ष लोकसभा में सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दे सकता है. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार महाभियोग प्रस्ताव लाए जाने की तैयारी के बीच मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ओम बिरला के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर अपनी बात रख सकते हैं. मालूम हो कि ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस के नेतृत्व में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है.

मजबूरी में जंग लड़ रहे- ईरान

तुर्किये-साइप्रस और अजरबैजान पर हमले से इनकार किया; इजराइली हमले में ईरान के नए सुप्रीम लीडर घायल

तेल अवीव/तेहरान।

ईरान ने कहा है कि वह मजबूरी में जंग लड़ रहा है, यह उसकी पसंद नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि जंग देश पर जबरन थोपी गई है। जब उनसे सीजफायर के लिए मध्यस्थता की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल इस तरह की बात करना गलत होगा। बघाई ने कहा कि इस समय सैन्य टकराव जारी है और ऐसे में देश की रक्षा के अलावा किसी दूसरे विषय पर चर्चा करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस जंग की शुरुआत नहीं की थी। उनके अनुसार देश को अपनी रक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने तुर्किये, साइप्रस और अजरबैजान पर हमले से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह इन देशों की दिशा में ईरान की जमीन से कोई हमला शुरू नहीं किया गया। इस बीच टाइम्स ऑफ इजराइल ने बताया कि ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुजतबा खामेनेई घायल हो गए हैं। उन्हें बीती रात ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था।

सीएम का बीजेपी पर धरना स्थल पर पर्चे बांटने का आरोप

टीएमसी कार्यकर्ताओं से कहा- पकड़कर पुलिस के हवाले करो

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी एजेंसियां कोलकाता में उनके धरनास्थल पर पर्चे बांट रही थीं। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें। मुख्यमंत्री बनर्जी पिछले तीन दिनों से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में शहर के बीचों-बीच धर्मतला में धरना दे रही हैं। उन्होंने राज्य की मंत्री शशि पांजा को भी इस मामले में पुलिस

में शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया। इन पर्चों में कथित तौर पर 14 मार्च को कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली का प्रचार किया गया था। पर्चों को बांटा जा रहा था। उन्होंने समर्थकों से कहा, किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यक्रम में ऐसे पर्चे बांटने का उन्हें अधिकार नहीं है। उन्हें पकड़ो और पुलिस के हवाले कर दो। बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, उन्हें जनता का समर्थन नहीं है। वे वोट चोर हैं। वे एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि पर्चे बांटने में शामिल लोग सामना होने के बाद वहां से भाग गए।

कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव अमान्य घोषित

हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामनिवास रावत होंगे नए एमएलए

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। विजयपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया गया है। बता दें कि पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में मुकेश मल्होत्रा पर चुनावी हलफनामे में आपराधिक रिकार्ड की जानकारी छुपाने का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया था कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान जो नामांकन दाखिल किया था, उसमें अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाई थी। मल्होत्रा पर 6 आपराधिक मामले दर्ज थे जबकि उन्होंने नामांकन में केवल 2 मामले ही बताए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी और तथ्यों को छिपाने को सही माना। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने आदेश देते हुए मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया। भाजपा के प्रत्याशी रहे रामनिवास रावत को दूसरे नंबर पर रहने पर विजयपुर से विधायक घोषित किया गया है।